



हिन्दी माध्यम का सर्वश्रेष्ठ संस्थान

# निर्माण IAS

## सामाजिक न्याय

### न्याय

#### संदर्भ

- कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा सरकार बनने पर न्यूनतम आय गारंटी योजना के तहत देश के बीस प्रतिशत परिवारों को 72 हजार रुपये प्रतिवर्ष दिए जाने का वादा किया गया।

#### पृष्ठभूमि

- इससे पहले वर्ष 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण में यूनिवर्सल बेसिक इनकम की अवधारणा पेश की गई थी।
- अब तक की सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के लाभों के हस्तांतरण के मामले में निराशाजनक प्रदर्शन के मद्देनजर जरूरतमंदों तक सार्वभौमिक रूप से वित्तीय सहायता की सीधी पहुँच सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है।
- यदि ऐसा होता है, तो इससे गरीबी-उन्मूलन की प्रक्रिया तेज होगी और गरीबों के लिए बेहतर ज़िंदगी सुनिश्चित की जा सकेगी। इसके लिए लाभार्थियों का जनधन, आधार और मोबाइल से जुड़ा होना जरूरी होगा।

#### न्यूनतम आय गारंटी योजना क्या है?

- न्यूनतम आय गारंटी योजना में यह प्रावधान होता है कि सरकार गरीबी रेखा के तय मानक के अनुसार उस श्रेणी के लोगों को एक निश्चित रकम देती है।
- यह एक न्यूनतम आधारभूत आय की गारंटी है जो केवल गरीब नागरिकों को बिना शर्त सरकार द्वारा दी जाती है।
- इसके लिये व्यक्ति की आय तय मानक के अनुसार होनी चाहिए और उसे उस देश का नागरिक होना जरूरी होता है, जहाँ इसे लागू किया जाना है।

#### यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI)

- यूनिवर्सल बेसिक इनकम की अवधारणा अपने मूल रूप में सभी नागरिकों के लिए वित्तीय सहायता के रूप में प्रति माह उस न्यूनतम राशि के बिना शर्त अंतरण पर बल देती है जिससे वो अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें और जिससे उनके लिए गरिमामय जीवन संभव हो सके।
- भारत में केंद्र सरकार की तरफ से प्रायोजित कुल 950 योजनाएँ हैं और जीडीपी बजट आवंटन में इनकी हिस्सेदारी लगभग 5% है।
- ऐसी ज्यादातर योजनाएँ आवंटन के मामले में छोटी हैं और प्रमुख 11 योजनाओं की कुल बजट आवंटन में हिस्सेदारी 50% है।
- सर्वे में यूनिवर्सल बेसिक इनकम को मौजूदा स्कीमों के लाभार्थियों के लिये विकल्प के तौर पर पेश करने का प्रस्ताव दिया गया है।

#### उद्देश्य:

- आर्थिक समीक्षा में सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना, नागरिकों को गरिमामय जीवन उपलब्ध कराना, गरीबी में कमी, रोजगार-सृजन एवं श्रम-बाजार में लोचशीलता के जरिये लोगों को कार्य-विकल्प उपलब्ध कराना।
- व्यापक प्रशासनिक दक्षता और वित्तीय समावेशन को इस स्कीम का लक्ष्य बताया गया है
- वर्तमान में चलायी जा रही लोक-कल्याणकारी योजनाओं की तुलना में यह योजना इन लक्ष्यों की प्राप्ति में कहीं अधिक सहायक है।

#### सैद्धांतिक आधार:

- सार्वभौमिकता, ताकि सभी नागरिकों को इसके दायरे में लाया जा सके;
- बिना शर्त अर्थात् न तो आय की शर्त और न ही रोजगार की शर्त;
- बुनियादी आय, ताकि बिना किसी अतिरिक्त आय गरिमापूर्ण जीवन जीना संभव हो सके।

### यूनिवर्सल बेसिक इनकम एवं न्यूनतम गारंटी योजना में अंतर

1. यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कांसेप्ट NDA सरकार ने 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण में दिया था जबकि न्यूनतम गारंटी योजना (MIG) की घोषणा कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गाँधी ने जनवरी में छत्तीसगढ़ के रायपुर में की थी।
2. UBI एक सार्वभौमिक अर्थात् सभी के लिए योजना है यानी यह लाभार्थियों की पहचान नहीं करती है जबकि MIG खासतौर पर देश के गरीब ग्रामीण और शहरी परिवारों के लिए लक्षित योजना है।
3. UBI योजना का पात्र होने के लिए लाभार्थी की आर्थिक स्थिति, रोजगार या बेरोजगार जैसे मापदंडों को ध्यान में नहीं रखा जायेगा। इसके उलट MIG स्कीम के लाभार्थी विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा चिन्हित किये जायेंगे।
4. UBI योजना में एक परिवार के हर सदस्य को अलग अलग सहायता दी जाएगी जबकि MIG योजना में तहत पूरे परिवार को इकाई माना जायेगा।
5. UBI योजना के तहत देश की 75% जनसँख्या को 7,620 रुपये प्रति व्यक्ति वार्षिक दिया जायेगा जबकि MIG के तहत देश के 25 करोड़ गरीबों को 6 हजार रुपये प्रति वर्ष दिया जायेगा।
6. UBI पर सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4.9% खर्च होगा जबकि MIG पर कुल परिव्यय सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2% होगा।

ध्यान रहे कि अर्थशास्त्री सुरेश तेंदुलकर ने देश के लोगों को पोषण की व्यवस्था के लिए न्यूनतम 7,620 रुपये प्रति व्यक्ति/वार्षिक देने की अनुशंसा दी थी।